उन्नीसवीं सदी में जब सील के शिकारी मैरिअन आइलैंड पर आए तो अनजाने में ही अनचाहे मेहमान भी साथ ले आए। अब दशकों बाद शिकारियों के साथ आए चूहों के वंशजों ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि, इस सब- एंटार्कटिक द्वीप की "यूनीक वाइल्डलाइफ" ही नष्ट हो रही है। ये मांसाहारी चूहे द्वीप पर घर बनाने वाली सी बड़र्स के अंडे, बच्चे और यहां तक कि, वयस्क सी बड़र्स को भी खा जाते हैं। इनका तरीका भी बेहद क्रूर है। चूहे पहले पक्षियों की त्वचा को कुतरते हैं फिर उन्हें खा जाते हैं। केपटाउन से 1370 मील दूर मैरिअन आइलैंड में इंसान नहीं रहते पर लाखों सी बड़र्स रहती हैं। जिसमें पैनग्विन की चार प्रजातियाँ और विश्व के टोटल "वॉण्डरिंग एल्बैट्रॉस" में से एक चौथाई इसी द्वीप पर हैं। वैज्ञानिकों को चिंता है कि, अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो इस द्वीप से पक्षी लुप्त हो सकते हैं। उनका अनुमान है कि, मैरिअन आइलैंड पर रहने वाली सी बड़र्स की 28 प्रजातियों में से 19 आगामी 30 वर्षों में लुप्त हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन के कारण समस्या और बढ़ रही है। तापमान बढ़ने से चूहों की प्रजनन दर व सरवाइवल रेट बढ़ी है। द्वीप को चूहों से मुक्त करवाने के लिए संरक्षणविदों ने एक महत्वाकांक्षी उन्मूलन प्रोजेक्ट शुरु करने की योजना बनाई है जिसे "माउस फ्री मैरिअन" नाम दिया गया है। यह अपनी तरह की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इसके तहत साउथ अफ्रीका से नौका द्वारा हैलीकॉप्टर्स भेजे जाएंगे। पायलट हैलीकॉप्टर्स से द्वीप पर चूहे मारने वाली दवा युक्त गोलियाँ गिराएंगे तथा कुछ दुर्गम स्थानों पर टीम के सदस्य स्वयं गोलियाँ डालेंगे। यह योजना पहले 2020 में शुरु होनी थी पर अब 2025 में शुरु होगी। अन्य द्वीपों पर किए गए ऐसे ही प्रयासों को मिश्रित सफलता मिली है। साउथ जॉर्जिया, जो साउथ एटलांटिक ओशन का ब्रिटिश द्वीप है, अब चूहों से मुक्त है। वर्ष 2011 में यहां 330 टन चूहा मारने वाली दवा गिराई गई थी। इंग्लैंड के ही एक अन्य द्वीप लंडी से भी 2002 -2004 के बीच चूहे भगाए गए थे, अब यहाँ पक्षी लौटने लगे हैं। तथापि, तमाम प्रयासों के बाद भी दक्षिण एटलांटिक के गॉफ द्वीप पर व्यापक चूहा उन्मूलन प्रयासों के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। संरक्षणविदों के अथक प्रयासों के बावजूद किसी द्वीप पर हर एक चूहे को मार डालना चूनौतीपूर्ण है।

मालपुरा में दो समुदायों के बीच एक घंटे हुई पत्थरबाजी से तनाव उपजा

पथराव में तीन कांस्टेबल सहित 19 लोग घायल हुये

- **तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने की बात पर दो समुदाय हुए आमने-सामने।**
- **घरों में घुसकर किये गये हमले के बावजूद पुलिस ने ना तो लाठी चार्ज किया और ना ही आंसू गैस जैसे सुरक्षा संसाधनों का प्रयोग किया।**
- **टोंक पुलिस लाइन सहित सात थानों व जिला कलेक्टर व एडीएम ने मालपुरा में डाला डेरा।**

मालपुरा, 23 अप्रेल (निसं)। अतिसंवेदनशील मालपुरा कस्बे के पुरानी तहसील में रविवार को दो समुदायों के बीच उपजे तनाव व एक घंटे से अधिक समय तक पुलिस की आंखों के सामने पत्थरबाजों द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर किये पथराव व घरों में घुसकर किये गये जानलेवा हमले के बावजूद पुलिस ने ना तो लाठी चार्ज किया और ना ही आंसू गैस जैसे सुरक्षा संसाधनों का प्रयोग किया जिसके चलते तीन कांस्टेबल सहित 19 महिला-पुरूष घायल हो गये।

पत्थरबाजों की भीड़ ने दो स्कूल टैम्पों में भी भारी तोड़फोड़ कर आग लगाने का प्रयास किया। मालपुरा अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद एक गंभीर घायल को चिन्ताजनक हालत में जयपुर रैफर किया गया। टोंक पुलिस लाइन सहित सात थानों का भारी पुलिस जाप्ता शहर में चप्पे-चप्पे पर तैनात कर मालपुरा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। मामले के अनुसार रविवार की दोपहर में पुरानी तहसील नागोरी मस्जिद के पास गुर्जरों के मौहल्ले में तेज रफ्तार में बार-बार मोटरसाइकिल दौड़ा रहे युवकों को महिलाओं द्वारा उलाहना दिये जाने के बावजूद बाइक सवार युवकों द्वारा बार-बार तेज रफ्तार मोटरसाईकिल दौड़ाने की हरकत से गुस्साई महिलाओं ने एक बाइक सवार को पकड़ खरी-खोटी सुनाते हुए दो थप्पड़ जड़ दिये।

महिला के हाथ में पहने कड़े की चोट लगने से युवक मामूली चोटिल हो गया। युवक के थप्पड़ जड़ने की मिली जानकारी के बाद गुस्साए एक पक्ष के सैंकड़ों लोगों ने दूसरे पक्ष पर पथराव व हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए पथराव व सैंकड़ों की संख्या में उमड़ी भीड़ को देख महिलाओं में चीख-पुकार शुरू हो गई। तो जवाब में मौजूद महिलाओं व कुछ लोगों ने भी पत्थरबाजों पर पथराव शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर हुए पथराव से 200 मीटर सीमा में सड़क व मकानों में पत्थरों का ढे र लग गया।

सूचना पर मौके पर पहुंचे डीवाईएसपी सुशील मान ने महज आधा दर्जन सिपाहियों के साथ पत्थरबाजों से समझाईश व रोकने का भरकस प्रयास किया। लेकिन पुलिस को देखकर पत्थरबाजों का आक्रोश कम नहीं हुआ। लगातार होते रहे पथराव से डीवाईएसपी बाल-बाल बच गये। लेकिन पथराव में कांस्टेबल रामजीलाल शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा, पुखराज पुत्र धर्मा, नाथु लाल घायल हो गये तो वहीं प्रेमचंद पुत्र रिद्धकरण गुर्जर के पांव में चाकू से वार किया गया। सुरजकरणी पत्नी रिद्धकरण, नाथु पुत्र भैरू गुर्जर, रतनी पत्नी नाथु गुर्जर, अयोध्या पत्नी रामदेव गुर्जर, फोरंता पत्नी राजू गुर्जर, कमला पत्नी काना गुर्जर, बिरधा पत्नी हरजी गुर्जर, मौसमी पत्नी जगदीश गुर्जर, गोगाराम पुत्र रिद्धकरण, संतोष पत्नी हेमराज बैरवा, सपना पुत्री सुखलाल, रोशनी पत्नी राजू, राकेश कुमार, सोहदरा, नर्बदा, नोरत माली, रंगलाल माली, ओमप्रकाश घायल हो गये। सभी घायलों को परिजनों ने मालपुरा अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल नाथु गुर्जर को चिन्ताजनक हालत में जयपुर रैफर किया गया।

मालपुरा में उपजे साम्प्रदायिक तनाव की घटना के बाद टोंक पुलिस लाइन, पीपलू डीवाईएसपी, देवली डीवाईएसपी सहित सात थानों का पुलिस जाप्ता शहर में तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, एडीएम शिवचरण मीणा, एसडीएम महिपाल सिंह, एएसपी राकेश कुमार बैरवा, डीवाईएसपी सुशील मान, तहसीलदार सहदेव मंडा, जिला परिषद अधिकारी देशल दान ने सम्पूर्ण घटनाक्रम का फीडबैक ले आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए मोर्चा सम्भाला। रात दस बजे समाचार लिखे जाने तक शहर में हालात शांतिपूर्ण तनाव के रहे। देर रात अजमेर रेंज आईजी रुपेन्द्र सिंह एवं संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने घटना स्थल का जायजा लिया। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा इतने बड़े साम्प्रदायिक तनाव की घटना के बावजूद एक भी गिरफतारी नहीं हो सकी।

पायलट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए फिर से आग्रह कर रहा हूं। 2013 से 2018 के बीच जब लोगों के बीच गए तो मुद्दा ये था कि, वसुंधरा के भ्रष्टाचार को खोलेंगे। पायलट ने कहा कि, हमारे प्रभारी रंधावा साहब संजीदा और समझदार व्यक्ति हैं। रंधावा साहब बाकी सब रिपोर्ट दे रहे हैं तो यह रिपोर्ट भी बनानी चाहिए कि, हमारे मंत्री और विधायकों पर कई तरह के आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पार्टी और सरकार की छवि को ठेस पहुंच सकती है। उसका भी संज्ञान लेकर खड़गे साहब और एआईसीसी के नेताओं तक पहुंचाना चाहिए, ताकि कार्रवाई करें।

कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी पद पर बैठा हो, किसी का चहेता हो, किसका दुश्मन हो, लेकिन अगर कहीं जांच के बाद तथ्य आते हैं तो हमें कार्रवाई करने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भेदभाव नहीं कर सकते। निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा।

मंत्री महेश जोशी पर आरोप लगाकर जान देने वाले रामप्रसाद मामले में पायलट ने कहा कि, मौत से पहले दिया गया बयान कोर्ट में मान्य होता है। जांच तो होनी चाहिए। हर व्यक्ति के नैतिकता के पैमाने अलग-अलग होते हैं। कौन इस्तीफा देता है, नहीं देता है, इस्तीफा लेते हैं, नहीं लेते हैं, यह मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जांच होनी चाहिए। जब इस तरह नाम आता है तो एक गंभीर मुद्दा हो जाता है और इस पर बहुत गहराई से जांच हो। सच्चाई तक हम पहुंचें। कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए।

बताया जाता है कि, सचिन पायलट ने अनशन को लेकर अपना स्टैंड दोहराते हुए कहा कि, बीजेपी राज के करप्शन पर जांच और कार्रवाई की मांग करना कांग्रेस विरोधी गतिविधि कैसे हो गया? इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने रविवार को कहा कि, मैंने भाजपा राज के भ्रष्टाचार की बात की, यह तो पार्टी के हित में था।

राजेन्द्र राठौड़ के जन्मदिवस पर एकत्रित रक्तदान ने बनाया देश में कीर्तिमान

- **नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन पर रक्तदान सप्ताह में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा रक्तदान किया, यह उपलब्धि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई।**

जयपुर, 23 अप्रेल (का.सं.)। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। इसका आयोजन मॉर्डन स्कूल मानसरोवर में हुआ और नेता प्रतिपक्ष ने यह अवार्ड प्राप्त किया। उनके जन्मदिवस के अवसर पर 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो रक्तदान सप्ताह मनाया गया। उसमें सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा रक्तदान किया जाना देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बन गया है।

मानव सेवा सप्ताह के संयोजक वासुदेव चावला और सह संयोजक प्रशांत टावरी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ का जन्मदिवस मानव सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया था, जिसमें 400 ब्लड डोनेशन कैम्पों के माध्यम से 69, 608 हजार से अधिक यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ था। उन्होंने बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पास एक निपुण टीम है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार दिन रात काम कर साक्ष्य इकट्ठे करती है। उसके बाद ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसी भी उपलब्धि को निष्पक्षता के साथ शामिल किया जाता है। इस बुक में नाम शामिल होना कम बात नहीं है,क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा और निष्पक्षता का विदेश भी कायल है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से संबद्ध है। जिसमें शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। राठौड़ ने यह कीर्तिमान क़ायम करने के बाद कहा कि ये राजस्थान के अपनों का प्यार है जिनके लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने बताया कि मैं पहली बार जब चिकित्सा मंत्री बना, तब एस.एम.एस. में एक अंत्योदय अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत थी। ब्लड बैंक में उसके ग्रुप का ब्लड उपलब्ध नहीं था। संयोगवश मैं एस.एम.एस. दौरे पर था। मुझे पता लगा तो मैंने पूछा इसका ब्लड ग्रुप क्या है। चिकित्सकों ने बताया ओ पोज़िटिव। तो मैंने कहा यही तो मेरा है। मैंने एक क्षण भी नहीं लगाया और उस अपरिचित निर्धन को मैंने ब्लड दिया। मेरे इस छोटे से प्रयास से उसकी जान बच गई। मैंने चिकित्सकों से कहा इसे मेरे बारे में मत बताना। उस घटना के बाद से ही मैं किसी न किसी बहाने रक्तदान शिविर लगवाने लगा। मेरी इस मिशन के बारे में जब सब कार्यकर्ता जान गए तो वे मेरे जन्मदिवस पर यह आयोजन रखने लगे और आज जीवन बचाने का यह सफ़र इस मुक़ाम तक पहुँच गया।

खालिस्तान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमृतपाल के समर्थन में किसी तरह के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए सामान्य सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने स्वर्ण मंदिर, अकाल तख्त और अमृतपाल के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है।

भगोड़े कट्टरपंथी उपदेशक और खालिस्तान नेता अमृतपाल सिंह के दो और सहयोगियों को 18 अप्रैल को पंजाब और दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त अभियान में पंजाब के मोहाली में गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल और उनके सहयोगियों पर वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने, हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले और कर्तव्य के वैध निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित कई आपराधिक मामलों के तहत मामला दर्ज किया गया था। अमृतपाल 18 मार्च से फरार चल रहा था जब उसके और उसके संगठन वारिस पंजाब दे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू की गई थी।

आंधी और तूफान के बीच मंत्रालयिक कर्मचारी महापड़ाव में डटे रहे

- **महासंघ का महापड़ाव सातवें दिन भी जारी, मंहगाई राहत शिविरों का बहिष्कार जारी रहेगा।**

जयपुर, 23 अप्रेल (का.प्र.)। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के आव्हान पर जारी सामूहिक अवकाश के साथ महापड़ाव आज सातवें दिन भी जारी रहा। आंधी और तूफान में भी कर्मचारी महापड़ाव में डटे रहे। आज महापड़ाव स्थल शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर पर कांग्रेस के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज महापड़ाव में पहुँचकर मंत्रालयिक कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि, मंत्रालयिक कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे हैं वो जायज हैं। जिन पर अतिशीघ्र मुख्यमंत्रीजी से बात कर आपसे चर्चा कराई जायेगी, मांग के पक्ष में निर्णय कराया जायेगा।

प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी ने कहा कि, मंत्रालयिक कर्मचारी पिछले 30 वर्षों से समानांतर कैडरों के समकक्ष वेतनमान एवं समान भर्ती की योग्यता की बात कर रहा है। प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र दाधीच ने बताया कि, कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2013 में कनिष्ठ सहायकों के वेतनमान में बढ़ोतरी करते हुए ग्रेड पे में बढ़ोतरी की थी लेकिन विगत भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2017 में पुन: छीनकर वेतनमान का पुन: निर्धारण करते हुए प्रत्येक मंत्रालयिक कर्मचारी को लगभग 6000 रुपये से आधिक का नुकसान पहुंचाया जिसे पुन: बहाली की मांग कर रहे हैं। राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंभु सिंह राठौड़ ने भी राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदौन्नति के 25 फीसदी कोटे को समाप्त करने का विरोध करते हुए कहा कि, सरकार राजस्व पटवार संघ के दबाव में 25 फीसदी कोटे को समाप्त करना चाहती है जिसका राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी विरोध कर रहा है, सभा में सभी 33 जिलों के जिला अध्यक्ष एवं तहसील अध्यक्ष के साथ जयपुर शहर के 50 विभागों के अध्यक्ष एवं हजारों की संख्या में मंत्रालयिक कर्मचारी उपस्थित रहे। महासंघ के जयपुर जिला अध्यक्ष मुकेश मुदगल ने बताया कि, सामूहिक अवकाश के साथ महापड़ाव जब तक जारी रहेगा तब सरकार मांगों के लिखित आदेश जारी नहीं कर देती है।

पहलवानों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन अभी तक उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

गौरतलब है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ अपनी शिकायतों को लेकर पहलवान जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय पहलवान और ओलंपियन बजरंग पूनिया ने बताया, "अभी तक कुछ हुआ नहीं है, यही कारण है। कनॉट प्लेस थाने में शिकायत भी दी है। दिल्ली पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई करेगी।" स्वाति मालीवाल ने पुलिस को जो नोटिस दी है, दिल्ली महिला आयोग को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की ओर से महिला पहलवानों के यौन शोषण की शिकायत प्राप्त हुई थी।

जयपुर में पुलिया पर पैट्रोल छिड़कर कोर्ट के मुंशी ने आत्मदाह किया

करधनी इलाके में रविवार को दोपहर तीन बजे जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर बैनाड़ पुलिया के ऊपर की घटना

- **मृतक जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में दादी का फाटक के पास फ्लैट में परिवार सहित रहता था और उसकी पत्नी भी वकील हैं।**
- **सूत्रों के अनुसार उसने कई लोगों से पैसे ले रखे थे साथ ही कुछ पारिवारिक विवाद भी बताया जा रहा है।**
- **काफी समय पहले उसका ओडिशा में एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद से वह करीब दस साल से बीमार चल रहा था।**

जयपुर, 23 अप्रेल (कासं)। राजधानी जयपुर के करधनी इलाके में रविवार को दोपहर तीन बजे जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर बैनाड़ पुलिया के ऊपर एक कोर्ट के मुंशी ने पैट्रोल छिड़कर खुद को आग लगा ली। इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार देवेंद्र शर्मा (45) मूलत: रींगस का रहने वाला था। जयपुर में वह मुरलीपुरा इलाके में दादी का फाटक के पास फ्लैट में परिवार सहित रहता था। पेशे से वह कोर्ट में मुंशी का काम करता था। उसकी पत्नी वकील हैं। रविवार दोपहर को करीब एक बजे वह अपनी कार लेकर घर से निकला था। इसके बाद दोपहर तीन बजे वह करधनी इलाके में जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर बैनाड़ पुलिया के ऊपर पहुंचा। यहां उसने गाड़ी से उतरने के बाद बोतल में रखा पैट्रोल खुद के ऊपर छिड़क लिया और आग लगा ली। आसपास से गुजर रहे लोग जब तक अपनी गाड़ी रोक कर उसे बचाने पहुंचे, तब तक वह पूरी तरह जल चुके था।

पुलिस ने बताया कि जहां पर मृतक ने आत्मदाह किया, वहां से उनका घर दिखाई देता है। वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर उसका घर है। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के भाई ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान की। पुलिस ने एफएसएल जांच के बाद शव को एसएमएस हॉस्पिटल भेज दिया जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मृतक ने आत्मदाह के लिए यही जगह क्यों चुनी। पुलिस ने उसके मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली रही है। उसी से पता चलेगा कि उसने घटना से पहले किस किससे बात की थी और उसका कया मूवमेंट क्या रहा था। पुलिस आसपास के पंपों पर भी पूछताछ कर रही है।

सूत्रों के अनुसार मृतक देवेन्द्र की की किसी से दुश्मनी नहीं थी। हालांकि उसका कुछ पारिवारिक विवाद जरूर चल रहा था। इसके अलावा उसने कई लोगों से पैसे ले रखे थे। इसके लिए देनेदारों के उसके पास तगादे के लिए फोन आते थे। उसने दादी के फाटक के पास जो फ्लेट ले रखा था उसका भी लोन बकाया था। काफी समय पहले उसका उड़ीसा में एक्सीडेंट भी हो गया था। इसके बाद से वह करीब दस साल से बीमार भी चल रहा था। साथ वह डिप्रेशन में भी था। उसके तीन बजे बच्चे है। इनमें एक लड़का और दो लड़की। उसका लड़का उदयपुर में पढ़ता है। एक लड़की जयपुर में जॉब करती है। वहीं एक बच्ची मंदबुद्धि है। उसने अपनी पत्नी को कोर्ट लाने और ले जाने के लिए एक लड़का भी रखा हुआ था। सूत्रों के अनुसार उसने एक भगवा रक्षा दल भी बना रखा था। जिसका वह खुद ही अध्यक्ष था। आत्महत्या से 6 घंटे पहले उसने फेसबुक पर पोस्ट भी किया। इसमें लिखा कि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जो भगवा रक्षा दल का प्रचार-प्रसार कर सकें। साथ ही दल को मजबूती प्रदान करने में आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। क्योंकि पद तो सबको चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी सौंपी जाए उसको उठाने का कोई प्रयास नहीं करता है। फायदे सबको चाहिए। भगवा रक्षा दल के नाम का कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसलिए थोड़े समय पहले मैंने समस्त कार्यकारिणी भंग कर दी थी। कुछ चुनिंदा लोगों को वर्तमान में जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थे, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब उसमें बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। जो भगवा रक्षा दल के प्रति उदासीन रहेगा, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है।

हैलिकॉप्टर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैलिकॉप्टर की विंग्स की चपेट में आ गये।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित सैनी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

यौन उत्पीड़न ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये कह रहे हैं।

अपनी बात कहते-कहते साक्षी मलिक इमोशनल हो गईं। उन्होंने कहा कि, हम कुश्ती का और अपने आगे आने वाले खिलाड़ियों का फ्यूचर दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इन 7 लड़कियों में इंटरनैशनल खिलाड़ी भी शामिल हैं, नाम नहीं बता सकते। कहा जा रहा है कि, हमने सबूत नहीं दिया। बृजभूषण शरण सिंह से सबूत क्यों नहीं लिया गया। पीड़ित लड़कियों की पूरी लाइफ सवाल है, अगर लड़की सामने आकर खड़ी हो जाएगी तो उसकी क्या लाइफ बचेगी।

'राजस्थान राइट टू हैल्थ गैर जिम्मेदाराना लोक लुभावन ...

- **यह एक्ट लाने वाले, सरकारी अस्पतालों से भी इसी प्रकार की वचनबद्धता की अपेक्षा कर रहे हैं, जहां डॉक्टरों तथा मैडिकल स्टाफ पर उनकी क्षमता से अधिक काम रहता है तथा जो काम के बोझ से बुरी तरह दबे रहते हैं।**
- **जहां तक निजी अस्पतालों का प्रश्न है, यह बिल उन्हें अन्य राज्यों में भेजने का सुनिश्चित उपाय है।**
- **क्या निजी मैडिकल कॉलेज तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल भविष्य में अन्य राज्यों में चले जाना पसंद नहीं करेंगे?**
- **क्या सरकारी तथा छोटे निजी अस्पताल इस अधिनियम द्वारा देय व्यापक अधिकारों को सच्चे अर्थों में पूरा कर पाने के लिए पर्याप्त होंगे?**
- **क्या राजस्थान, जिसके पास राइट टू एजुकेशन के तहत, निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के 25 प्रतिशत कोटा के लिए भी संसाधनों की कमी सामने आ रही है, के पास इतने संसाधन हैं कि, वह मरीजों को निःशुल्क दी गयी चिकित्सा सुविधा के लिए निजी अस्पतालों को भरपाई कर सकेगा?**
- **राज्य का कोई भी निवासी, निजी अस्पतालों को, उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी सेवा के लिए भुगतान क्यों करेगा, जबकि, नए अधिनियम में उसे निःशुल्क चिकित्सा की गारंटी दी गई है।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाहिर है, और हैरानी वाली बात भी नहीं है कि विधानसभा द्वारा पारित राइट टू हैल्थ बिल के क्रियान्वयन का पूरा भार मौजूदा अस्पतालों पर डाल दिया गया है। जहां तक सार्वजनिक अस्पतालों का प्रश्न है, ये सभी रोगियों के आऊटडोर एवं इनडोर विभाग सेवाएं, जांचे, आपातकालीन आवागमन लेजाना, चिकित्सा प्रक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। जहां तक निजी अस्पतालों का प्रश्न है, यह बिल इन्हें किसी प्रकार के भुगतान एवं पुलिस क्लियरेंस के बिना ही, सभी लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, जिसमें प्रसव- सुविधा एवं इलाज भी शामिल है, उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य के निवासियों को किसी भी अस्पताल से नि:शुल्क चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने का भी प्रावधान है एक्ट में।

यह एक्ट लाने वाले सरकारी अस्पतालों से भी इसी प्रकार की वचनबद्धता की अपेक्षा कर रहे हैं, जहां डॉक्टरों तथा मेडिकल स्टाफ पर पहले से ही उनकी क्षमता से अधिक कार्यभार रहता है तथा जो काम के बोझ से बुरी तरह दबे रहते हैं। जहां तक निजी अस्पतालों का प्रश्न है, यह बिल उन्हें राजस्थान छोड़कर अन्य राज्यों में जाने को बाध्य करने का सुनिश्चित उपाय है। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं था कि राजस्थान के सभी निजी अस्पतालों ने, इस बिल के विधानसभा में पारित होने से पहले ही हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया था।

निजी अस्पतालों के पूर्ण शटडाऊन के 17 दिन बाद, राज्य सरकार 4 मार्च को समझौता टेबल पर आई तथा हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की प्रमुख तथा मूल मांगे (हालांकि पूरी नहीं) मान लीं। सरकार इस बात पर सहमत हो गयी कि वे सभी मल्टी स्पेशियलिटी निजी अस्पताल इस कानून से बाहर रहेंगे, जो 49 या इससे कम शय्या वाले हैं, तथा जिन अस्पतालों ने जमीन या भवन के रुप में सरकारी सहायता नहीं ली है, अर्थात ये चीजें रियायती दर पर प्राप्त नहीं की हैं। लेकिन यह कानून इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तथा पीपीपी मोड पर स्थापित अस्पतालों पर लागू होगा जिन्हें जमीन रियायती दर पर दी गयी है तथा जो ट्रस्टों द्वारा संचालित हैं।

लेकिन यह समझौता भी कई सवाल खड़े करता है। क्या निजी मेडिकल कॉलेज तथा ट्रस्ट संचालित अस्पताल भविष्य में अन्य राज्यों में चले जाना पसंद नहीं करेंगे? क्या सरकारी अस्पताल और इसमें शामिल निजी अस्पताल इस अधिनियम द्वारा देय व्यापक अधिकारों को सच्चे अर्थों में प्रदान कर पाएंगे? क्या राजस्थान, जिसके पास राइट टू एजुकेशन के तहत, निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों के 25 प्रतिशत कोटा के लिए भी संसाधनों की कमी सामने आ रही है, के पास इतने संसाधन हैं कि वह मरीजों को नि:शुल्क दी गयी चिकित्सा सुविधा के लिए निजी अस्पतालों को इलाज के खर्च का भुगतान कर सकेगा? राज्य का कोई भी निवासी निजी अस्पतालों को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी भी सेवा के लिए भुगतान क्यों करेगा, जब नये अधिनियम में उन्हें नि:शुल्क चिकित्सा की गारंटी दी गयी है।

ऐसी लोक-लुभावन योजनाओं जिन पर निरन्तर तथा बहुत बड़ा खर्च होता रहता है, विचार करते समय सरकारों पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। कार्यकाल के अंत के आस-पास, अगर चुनावों के बाद सत्ता से हट जाने की संभावना दिखाई दे रही हो, तो ऐसी योजनाओं के प्रति इस उम्मीद में, एक अतिरिक्त लोभ-लालच पैदा होने लगता है कि हो सकता है कि यह योजना संभावित पराजय को विजय में बदल दे। लेकिन नागरिक वर्ग के व्यापक हित में इस प्रकार के प्रलोभन को रोका ही जाना चाहिए।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908